* 20th Year
* Issue: 100
* 09.08.2026 (SUNDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को दिया विकसित भारत का विजन

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ढ्ढञ्ज) दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह आज आपके परिवार वाले गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सभी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों को उनकी उपलज़्धियों के लिए मेडल मिले हैं। मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूँ। हालाँकि, अगर उनमें कुछ और लड़कियाँ भी होतीं तो और भी अच्छा होता। माफ़ कीजिए। सिर्फ़ एक या दो ही ज़्यों? और भी होनी चाहिए थीं।

इसके साथ ही मोदी ने कहा कि आज ढ्ढञ्ज दिल्ली में ढ्ढ से जुड़े कुछ नए पहल भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि आज आप सभी और सारे छात्रों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। हर छात्र के मन में आने वाले कल की अपनी-अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने नए ह्यह्लड्डह्म्ह्लह्वश्च का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले प्रतियोगी परीक्षा का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है। लेकिन इन सबके बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। मोदी ने कहा कि वो दिन याद करिए जब आपका ढ्ढञ्ज दिल्ली में पहला दिन था और एक आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की ही तो बात है, जब अभिविन्यास हुआ था और अब ये दीक्षांत समारोह का समय भी आ गया। ह्लह्द्गठ्ठह्लड्डह्लद्बश्ठ्ठ से ष्टशठ्ठ1शष्ड्डह्लद्बश्ठ्ठ की इस यात्रा का आपको भरपूर ह्यड्डह्ल-द्वह्यद्बड्डष्ह्लद्बश्ठ्ठ भी होगा। और साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए ष्द्धड्डश्चह्लद्गह्म् की शुरुआत का उत्साह भी होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। कोई

नहीं कह सकता कि आज से 20-30 साल बाद ज़्या होगा। लेकिन यह बदलती दुनिया और टेज़्नोलॉजी नए मौके लाएगी, और जो सीखेगा, वही जीतेगा। जो लोग नई स्थितियों और चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, वे चुनौतियों को मौकों में बदल देते हैं। यही बात आपने ढ्ढञ्ज दिल्ली में सीखी है। लेकिन जब-जब बदलाव का दौर आता है, तब-तब चुनौतियां भी आती हैं और नए अवसर भी पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा। जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा, तो ये कैंपस लाइफ, आपके दोस्त, टीचर्स, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके श्चह्म्शद्धद्गह्यह्यशह्म्ह्य जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिज़्मेदारी उठाई और आपका ये ढ्ठह्यह्लद्ब जो धीरे-धीरे आपका घर बन गया। आप अपनी हर ह्यह्वष्द्गह्यह्य में इन सबको याद करेंगे, इन सबके लिए thankful होंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपके मन के किसी कोने में कुछ और भी चल रहा हो। मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हर छात्र के मन में कुछ न कुछ विचार ज़रूर चल रहे होंगे। आप में से हर किसी के मन में भविष्य को लेकर कोई न कोई सोच या विज़न ज़रूर होगा।

उन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई चुनौती बड़ी लगे, तो घबराएं नहीं। उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। याद कीजिए जब सिमुलेशन में समाधान खोजने में घंटों या दिनों का समय लग जाता था, लेकिन फिर आपने समस्या को हल किया और कुछ नया सामने लाए। इसी तरह, जीवन में भी समस्याएं आएंगी, लेकिन उनके साथ-साथ नए अवसर भी आएंगे। बस आपको सतर्क रहना होगा। स्ख्द्बद्द में ष्ह्वह्म्-शह्यद्बह्ल4 बनाए रखिए... अपनी learning instinct को जगाए रखिए। जो बातें बिना सोचे-समझे स्वीकार कर ली जाती हैं... उन्हें परखिए। उन पर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए। उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए।

मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि हर पीढ़ी को अपने समय की खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपनी राष्ट्रीय ज़िज़्मेदारी भी निभानी पड़ती है... अगले 30 से 35 सालों में आप जो कुछ भी करेंगे, उसका असर %विकसित भारत% की ओर हमारे सफ़र पर पड़ेगा। इसलिए, आपके हर फ़ैसले का आधार यह भी होना चाहिए कि इससे देश को ज़्या फ़ायदा होगा? इससे देश की कौन-सी ज़रूरतें पूरी होंगी?

मथुरा विवाद: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में वार्ता बेनतीजा, १८ को पुन: होगी अहम चर्चा

मथुरा ०८/०८ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच स्थानीय स्तर पर शुक्रवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही। अधिवक्ताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ताओं के अनुसार, दोनों पक्षों ने विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एज़्ट) की अदालत में अपनी-अपनी दलीलें रखीं हालांकि, किसी सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका। अब दोनों पक्षों के बीच 18 अगस्त को फिर वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि अगर इस बार भी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता है तो मामले में उच्चतम न्यायालय से ही निर्णय की उज़्मीद होगी।

मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान और मंदिर परिसर स्थित शाही ईदगाह को लेकर पिछले कई साल से विवाद बना हुआ है। करीब डेढ़ दर्जन वादकारियों ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त बताते हुए दावा किया कि शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 13.37 एकड़ भूमि पर स्थित है। उन्होंने उक्त भूमि हिंदू पक्ष को वापस सौंपने का अनुरोध किया है। इन दावों से संबंधित कई मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं।अधिवक्ताओं ने बताया कि इन मामलों को सुलह के माध्यम से हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरिये आपसी वार्ता कर समाधान निकालने का निर्देश दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत में चार जुलाई को हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को उक्त भूमि से ईदगाह हटाकर किसी अन्य स्थान पर निर्माण के लिए भूमि उपलज़्ध कराने का प्रस्ताव दिया था हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा था। इसके बाद शुक्रवार को फिर वार्ता की तारीख तय की गई थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार भी उनकी ओर से मुस्लिम पक्ष को अन्यत्र भूमि उपलज़्ध कराने और विवादित भूमि मंदिर न्यास को सौंपने का सुझाव दिया गया।

वहीं, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हिंदू पक्ष के प्रस्ताव को खारिज करते हुए वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और इंतजामिया कमेटी के बीच हुए समझौते पर कायम रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो अदालत को ही तथ्यों पर विचार कर यह तय करना चाहिए कि किस पक्ष का दावा सही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में समझौता वार्ता की आवश्यकता नहीं है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एज़्ट) अरविंद कुमार ने अंतिम प्रयास के तौर पर एक अन्य विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए दोनों पक्षों को 18 अगस्त को उपस्थित होकर मामले का समाधान निकालने का अवसर दिया गया है।

प्रशांत किशोर संग सुनेत्रा पवार की भेंट से भाजपा में बेचैनी, महायुति में भी खलबली

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (ह्रष्टक्क) के नेताओं और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के बीच हुई बैठक से पार्टी और उसके %महायुति% सहयोगियों के बीच हलचल मच गई। बैठक के बाद ऐसी अटकलें तेज़ हो गईं कि किशोर—जिनकी जन सुराज पार्टी ने इस हज़्ते की शुरुआत में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी—महाराष्ट्र में पार्टी नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं और राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे को हटाकर किसी और को लाना चाहते हैं। हालांकि, तटकरे ने पार्टी के नए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर किशोर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, ज़्योंकि किशोर खुद एक पार्टी चला रहे हैं — इससे पार्टी के अंदर मतभेद और गहरे हो गए हैं।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी को किसी चुनावी रणनीतिकार की ज़रूरत नहीं है। उनका तर्क था कि चुनाव सलाह या कैंपेन थीम से नहीं, बल्कि आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से जीते जाते हैं।

गुरुवार को किशोर ने ह्रष्टक्क की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके बड़े बेटे पार्थ

से मुलाकात की, जो राज्यसभा सांसद भी हैं; उनके दूसरे बेटे जय ने वर्चुअल तरीके से बैठक में हिस्सा लिया।

माना जा रहा है कि पवार परिवार ने किशोर के साथ पार्टी के रोडमैप पर चर्चा की, जिसमें किशोर ने सुझाव दिया कि तटकरे को बदल दिया जाए ज़्योंकि वे महाराष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर पर्याप्त काम नहीं कर रहे थे। रायगढ़ से लोकसभा सांसद तटकरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ज़्या बातचीत हुई। हम प्रैज़्टिकल लोग हैं और थ्योरी में यकीन नहीं रखते। सच कहूं तो, मुझे रणनीतिकारों की ज़रूरत नहीं है ज़्योंकि मैं ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। किसी गांव का दौरा करने से ही मुझे वहां के लोगों का मूड पता चल जाता है।दूसरी ओर, किशोर की ह्रष्टक्क नेताओं के साथ हालिया मुलाक़ात से उनकी सहयोगी पार्टी क्चछ्वक्क नाराज़ हो गई।

ना घट रही माइलेज ना हो रहा नुकसान, ई20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): देश भर में हुए टेस्ट के बाद तेल कंपनियों ने कहा कि ई20 पेट्रोल की क्वालिटी तय मानकों के दायरे में है और इसमें मिलावट की आशंकाएं बेबुनियाद हैं। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को कहा कि श्व20 पेट्रोल के देशव्यापी टेस्ट में ज़्यादा नमी या ज़्लोराइड के कारण होने वाली खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे केंद्र सरकार की इथेनॉल-ज़्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर जताई जा रही चिंताओं को चुनौती मिली है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पूरी सप्लाई चेन में ज़्यूल की क्वालिटी तय सीमाओं के भीतर रही, जबकि पुरानी गाड़ियों के लिए ज़्लेंडेड ज़्यूल के उपयुक्त होने और माइलेज पर इसके असर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि केंद्र सरकार ने ज़्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल में ज़्लोराइड की मात्रा के लिए नियम तय किए हैं। बयान के अनुसार, नियमों का पालन

सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों, डिस्टिलरियों, डिपो, टर्मिनल और रिटेल आउटलेट्स पर लगातार निगरानी की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा, हर रिटेल आउटलेट पर दिन में 8-12 बार पानी की मिलावट और घनत्व (डेंसिटी) की जांच करके, मोबाइल ज़्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब तैनात करके और ज़्यूल लैब के ज़रिए नतीजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करके क्वालिटी की निगरानी को और मज़बूत किया गया है। इसलिए, तीनों कंपनियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में पूरी सप्लाई चेन शामिल थी और इस बात पर ज़ोर दिया कि ईंधन की गुणवज़्ा लगातार तय सीमाओं के भीतर बनी हुई है।

रिफाइनरी से लिए गए 100 से ज़्यादा पेट्रोल सैंपल में ज़्लोराइड का लेवल 1 पार्ट पर मिलियन (श्चश्चद्व) या उससे कम पाया गया, जबकि पिछले 10 दिनों में 80 डिस्टिलरी से लिए गए इथेनॉल सैंपल में ज़्लोराइड की मात्रा 3 श्चश्चद्व से कम पाई गई। ह्रद्वष्ह्य ने बताया कि देश भर के डिपो और टर्मिनल से लिए गए 80 से ज़्यादा सैंपल में भी ज़्लोराइड की मात्रा 3 श्चश्चद्व से कम पाई गई। ह्रद्वष्ह्य ने कहा कि रिटेल आउटलेट पर पिछले कुछ दिनों में टेस्ट किए गए 160 से ज़्यादा श्व20 सैंपल में ज़्लोराइड का लेवल 0-3 श्चश्चद्व की रेंज में पाया गया, जो कई सौ श्चश्चद्व होने के दावों के उलट है। ज़्लोराइड का लेवल ज़्यादा होने के सिर्फ़ दो अलग-अलग मामले सामने आए, जिनमें सप्लाई तुरंत रोक दी गई; सप्लाई फिर से शुरू करने की इजाज़त देने से पहले मामले की असल वजह का पता लगाने और सुधार के उपाय करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

मुर्शिदाबाद के सांसदों ने सीएम अधिकारी से मुलाकात की

मुर्शिदाबाद ०८/०८ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दो सांसदों ने शनिवार को मुज़्यमंत्री से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर चिंता जताई। राज्य सचिवालय नबान्न में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अबू ताहिर खान ने आरोप लगाया कि राज्य में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। खान ने कहा, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।बंगाल में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कृपया इसे रोका जाए। हमें नमाज अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। खान के साथ जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, अदालत के निर्देशों का निश्चित रूप से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना सही नहीं है। हमने सरकार से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया है। साल 2024 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मुर्शिदाबाद से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले खान ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो रही है। उन्होंने कहा, हमने मुज़्यमंत्री से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई रोकने की अपील की है। दोनों सांसदों ने मुस्लिम बहुल जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) न्यायाधिकरणों में बड़ी संज़्या में लंबित मामलों को लेकर भी मुज़्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।

झारखंड पेपर लीक: सरकार संग वार्ता बेनतीजा रही, प्रदश्रन जारी रखने का ऐलान

रांची ०८/०८ (संवाददाता): भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार ने शनिवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। प्रदर्शनकारी अज़्यर्थियों ने अपनी सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। सरकार की पांच सदस्यीय समिति, जिसमें तीन मंत्री शामिल थे, ने सबसे पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारी गुट से मुलाकात की।

इस मुद्दे को लेकर महतो के अनशन का शनिवार को सातवां दिन है। इसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई, एसीएस और जेसीएम के प्रतिनिधिमंडलों से भी बातचीत की। इससे पहले शुक्रवार रात को सरकार ने जेपीएससी/जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भी इसी तरह की वार्ता की थी।

सरकार की ओर से गठित समिति के सदस्य और राज्य मंत्री संजय प्रसाद यादव ने लगातार हुई बैठकों के बाद कहा, " प्रदर्शनकारी अज़्यर्थियों की मांगें जायज हैं। हम इन मांगों को मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे।" सज़ारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की छात्र इकाई झारखंड छात्र मोर्चा (जेसीएम) ने सरकार के सामने पांच मांगें रखीं, जिनमें 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की मांग भी शामिल है। एनएसयूआई ने सरकार के समक्ष छह मांगें रखीं।संगठन के प्रवक्ता संजीव शाह ने बताया कि इनमें संदेह

के घेरे में आई सभी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की 90 दिनों के भीतर सीआईडी जांच और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की तर्ज पर झारखंड परीक्षा एजेंसी (जेटीए) स्थापित करने की मांग शामिल है। सरकार की समिति की पहली बैठक महतो गुट के जेपीएससी-जेएसएससी अज़्यर्थी मंच के साथ हुई, जो करीब दो घंटे तक चली। मंच के एक नेता ने बैठक के बाद कहा, "सरकार ने हमारी ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत हमारी सभी मांगें पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।" राज्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और छात्रों की ओर से बताई गई भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों का जल्द समाधान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए अज़्यर्थियों से सुझाव लेने के लिए एक ई-मेल आईडी जारी की है। पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन का शनिवार को 15वां दिन है। देवेंद्र नाथ महतो ने 'पीटीआई-भाषा' कहा, " हम 14वीं झारखंड पीएससी सिविल सेवा परीक्षा और उस एजेंसी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि छात्र पिछले दो सप्ताह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार को उनकी मांगें तुरंत पूरी करनी चाहिए। महतो ने कहा, "सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार इन मांगों पर ज़्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। अगर शुक्रवार को 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद ही सरकार मांगें मान लेती तो शनिवार की बैठक की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्योंकि हमारी मांगें लगभग समान हैं।" उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, " मेरी तबीयत दिन-ब-दिन खराब हो रही है। रक्तचाप और शुगर का स्तर गिर रहा है। डॉज़्टर ने छाती में संक्रमण की जानकारी दी है और अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। अगर यही स्थिति जारी रही तो यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अब मैं केवल धीरे-धीरे सुन, सोच और बोल पा रहा हूं।" प्रदर्शनकारी अज़्यर्थी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच या तो केंद्रीय अन्वेषण ज़्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए या फिर राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृज़ न्यायाधीशों की समिति गठित की जाए।

विविध समाचार

स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर गोली खाई, आप अंडों से डर गयीं? सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा पर की तीखी टिप्पणी

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): राजनीति में कदम रखने के बाद विरोध, नारे, सवाल और कभी-कभी विरोधियों के तंज झेलना शायद लोकतांत्रिक जीवन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अगर विरोध का हथियार 'अंडा' बन जाए और उससे बचने के लिए सांसद पुलिस के सामने वर्चुअल पेशी की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, तो अदालत का चुटीला सवाल आना तय है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। अदालत ने उनकी उस मांग में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित आपज़्ज़िजनक पोस्ट से जुड़े मामले में पुलिस के सामने ऑनलाइन माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दज़्ज़ा और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने साफ संकेत दिया कि वह कलकज़्ज़ा हाई कोर्ट के उस निर्देश में दखल देने के पक्ष में नहीं है, जिसके तहत कृष्णानगर की सांसद को जांच में शामिल होने और पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि सांसद को जांच अधिकारी के सामने वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका तर्क था कि पुलिस ने उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के थाने में उपस्थित होने को कहा है और पिछली बार वहां जाने पर उन्हें विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा था। वकील ने अदालत को बताया कि पहले उन्हें धमकी दी गई कि उन पर अंडे फेंके जाएंगे और बाद में वास्तव में अंडे भी फेंके गए। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विरोध का 'प्रोटीन पैकेज' भी जमीन पर पहुंच गया। इसी दलील के जवाब में पीठ ने वह टिप्पणी की, जिसने पूरे मामले को कानूनी सुनवाई से निकालकर राजनीतिक बहस का विषय बना दिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दज़्ज़ा ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पूछा कि राजनीति में उतरने के बाद सांसद अंडों से ज़्यों डर रही हैं? अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाईं। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी

ही नहीं चाहिए थी। अदालत की इस टिप्पणी ने साफ कर दिया कि राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक विरोध के जोखिम और आपराधिक जांच में कानून के मुताबिक सहयोग, दोनों को अलग-अलग कसौटियों पर देखा जाना चाहिए। उधर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने याचिका वापस ले ली। इसके बाद अदालत ने इसे 'वापस ली गई' याचिका के रूप में खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मूल आरोपों पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, बल्कि वर्चुअल पेशी की मांग पर राहत देने से इंकार किया। हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद कलकज़्ज़ा हाई कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को फिलहाल ष्थद्गह्ल्ष्द्ब1द्ग ड्डष्ह्लद्बशठ्ठ यानी पुलिस की ओर से कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी थी, लेकिन साथ ही जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। हाई कोर्ट ने यह सुरक्षा 5 अज़्टूबर तक दी है, बशर्ते सांसद जांच में सहयोग करती रहें। मामले की अगली सुनवाई 1 अज़्टूबर को निर्धारित है।

हाई कोर्ट ने यह भी गौर किया था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। इसी आधार पर उन्हें फिलहाल गिरज़्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। लेकिन सुरक्षा का मतलब जांच से छुट्टी नहीं है और यही बात सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी केंद्रीय रूप से उभरकर सामने आई। हम आपको बता दें कि मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हगोलबेरिया थाने में दर्ज केस से संबंधित है। महुआ मोइत्रा ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने और पुलिस की कठोर कार्रवाई से संरक्षण की मांग की थी। यह विवाद एक कथित भड़काऊ पोस्ट से जुड़ा है, जिसे लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू यही है कि जिस सांसद की पहचान संसद में तीखे सवालों, आक्रामक तेवर और बेबाक बयानों के लिए होती है, वही अब अंडे फेंके जाने की आशंका को लेकर पुलिस स्टेशन जाने से बचने की कोशिश करती नजर आईं। हालांकि कानूनी रूप से अंडे फेंका जाना कोई मामूली बात नहीं है और किसी भी व्यक्ति को हिंसक या अपमानजनक विरोध से सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को जांच में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की जिज़्मेदारी से बचने का पर्याप्त आधार नहीं माना।

बहरहाल, अदालत की टिप्पणी ने एक राजनीतिक व्यंग्य जरूर छोड़ दिया है कि सियासत की राह में फूलों की उज़्मीद लेकर उतरने वालों को कभी-कभी अंडों की बारिश भी झेलनी पड़ती है। महुआ मोइत्रा के लिए फिलहाल संदेश स्पष्ट है। हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग का रास्ता दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रास्ते पर वर्चुअल शॉर्टकट देने से इंकार कर दिया है। अब गेंद फिर उसी पाले में है जहां से मामला शुरू हुआ था यानि पुलिस की जांच और अदालत की अगली सुनवाई।

मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में होगा सियासी उबाल, कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): एक अहम घटनाक्रम में, कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा और लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया और उनसे 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में मौजूद रहने को कहा, ज़्योंकि दोनों सदनों में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी है। तीन-लाइन वाले व्हिप में, राज्यसभा में कांग्रेस के मुज़्य व्हिप ने कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त, 2026 को राज्यसभा में बहुत ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों से यह भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके सांसद इन तीनों दिनों में मौजूद रहें। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए यह व्हिप (2द्धद्बश्च) तब जारी किया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले हज़्ते संसद में विवादित स्नष्टक्र संशोधन बिल पर चर्चा और उसे पास कराने की प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर विचार करने

की भी चर्चा है। अगले हज़्ते के संभावित सरकारी कामकाज की सूची बताते समय, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने स्नष्टक्र संशोधन बिल और परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल का कोई ज़िक्र नहीं किया। इस बीच, केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए विपक्षी दलों से बातचीत की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी संपर्क किया है। संसद में विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद, संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और राहुल गांधी के बीच तीन बार बातचीत हुई है।पता चला है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा है, जबकि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है और कहा है कि वह %इंडिया% (ड्डह्लष्टद्ध) गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेंगे। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी॰ह्लद्ध को बताया कि वे कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं ज़्योंकि वह मुज़्य विपक्षी पार्टी है और केंद्र सरकार पहले ही इस प्रस्तावित विधेयक पर कई राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुकी है। सरकार ने %इंडिया% गठबंधन की प्रमुख पार्टियों, जैसे समाजवादी पार्टी और ह्रष्टक्(स्क), से भी संपर्क किया है और बताया है कि ष्टस्न्य ने कोई अंतिम फैसला लेने से पहले कुछ आश्वासन मांगे हैं।

सुखवीर बादल ने महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग की

नयी दिल्ली ०८/०८ (संवाददाता): शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को यहां अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की। बैठक के बाद स्नष्ठ प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ङ्ग पर एक पोस्ट में कहा कि शिरोमणि अकाली दल को सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने महिलाओं के सज़्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है।

बादल ने कहा कि संसद के सामने अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद, स्नष्ठ ने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की भी मांग की, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने लिखा कि शिरोमणि अकाली दल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे भारत सरकार ने सदन में सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए पेश किया था। बादल ने पोस्ट में कहा कि पार्टी ने ज़ोर दिया कि महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए। सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र में विपक्षी नेताओं और ह्ष्ठ सहयोगियों से संपर्क करके, 2029 में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संज़्या बढ़ाकर 816 करने के लिए संविधान संशोधन बिल पास कराने की नई कोशिश कर रही है।

पिछली बार के सत्र में यह संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया था। मैंने आपको लिए गए फैसलों के बारे में बताया है, खासकर महिला आरक्षण बिल को लागू करने और सीटों की संज़्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए परिसीमन के फॉर्मूले के बारे में... शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष किसी भी मामले पर, या पंजाब के व्यापक हित में उनसे (क्क्रूसे) मिल सकते हैं।

झारखंड में भर्ती परीक्षा विवाद पर छात्रों ने सरकार को सौंपी 10 सदस्यों की नई सूची

रांची ०८/०८ (संवाददाता): भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को 10 सदस्यों वाले नए प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी। यह प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के साथ बातचीत करेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड लोक सेवा आयोग-झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुधार मंच ने बताया कि सरकार की ओर से पहले भेजे गए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर आपज़्ज़ि जताए जाने के बाद नयी सूची सौंपी गई है।

पुराने प्रतिनिधिमंडल में एक अधिवक्ता और दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। नए प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। झारखंड में भर्ती

परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया।

इस दौरान छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जबकि दो छात्र संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा तक मार्च निकाला।

छात्रों से बातचीत के लिए गठित पांच सदस्यीय सरकारी समिति के सदस्य और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की ओर से प्रतिनिधिमंडल में एक अधिवक्ता को शामिल किए जाने पर आपज़्ज़ि जताने के बाद नयी सूची सौंपी गई। बातचीत का फैसला मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान के एक दिन बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ चर्चा के लिए सरकार तैयार है।

सुदिव्य कुमार ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, यह आंदोलन छात्रों का है और सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या झारखंड का कोचिंग माफिया इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो सरकार ऐसा नहीं होने देगी।

रांची में जेपीएससी आंदोलन, नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, बोली-आंसू गैस और पेलेट ने नहीं डरे, इससे भी नहीं डरेंगे

रांची ०८/०८ (संवाददाता): शुक्रवार को रांची में झारखंड विधानसभा की ओर हो रहे विरोध मार्च के दौरान, एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यह मार्च, 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र प्रदर्शनों का हिस्सा था।

इस घटना के बाद स्याही से सनी अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए बोरा ने आरोप लगाया कि रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान ऋस्स-ब्द्धक्क के गुंडों ने उन पर और लगभग 20 अन्य महिलाओं पर यह लिक्विड फेंका था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए स्याही दूसरों को शर्मिंदा करने का एक ज़रिया है, लेकिन हम स्याही से ही भविष्य लिखेंगे! उन्होंने

आगे कहा, मैं गर्व के साथ इस स्याही को पहने हुए हूँ। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया; जब हम तब नहीं डरे, तो यह मामूली स्याही हमारा ज़्या बिगाड़ सकती है? उन्होंने कहा कि झारखंड और पूरे देश में होने वाली हर परीक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। जब भी पेपर लीक होता है, तो इसकी ज़िज़्मेदारी सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती। संबंधित सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि सिस्टम में शामिल और गड़बड़ी व भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही सभी प्राइवेट एजेंसियों को हटाया जाए... हम 10 तारीख को छात्रों द्वारा की गई अपील का समर्थन करेंगे और छात्रों के भविष्य के लिए खड़े रहेंगे। स्याही फेंकने के आरोपी व्यक्ति को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था, तो उसने पत्रकारों से कहा कि मुझे नेहा बोरा पसंद नहीं है ज़्योंकि वह उमर खालिद का समर्थन करती हैं। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैंने उन पर स्याही फेंकी। वे सभी देश-विरोधी हैं। बोरा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में हो रहे छात्र विरोध-प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।

पीएम मोदी के वादे के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने से निराश हैं उमर अब्दुल्ला

कश्मीर ०८/०८ (संवाददाता): जज़्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वादे के अनुरूप बहाल किए जाने में हो रही देरी पर मुज़्यमंत्री उमर अज़्दुल्ला ने शनिवार को गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर ''गुस्सा और निराशा'' केवल मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्हें खुद भी इसकी वजह से ''बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान'' उठाना पड़ा है। अज़्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी से जज़्मू-कश्मीर की जनता में निराशा पैदा हुई है, जो केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है।

अज़्दुल्ला ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, ज़्योंकि वह लगातार ''उन गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, जो उनकी नहीं हैं।'' मुज़्यमंत्री ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल कराने की उज़्मीद में केंद्र सरकार के साथ रचनात्मक संबंध बनाने की उनकी शुरुआती रणनीति ने स्थानीय लोगों के बीच

उनकी राजनीतिक साख को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। अज़्दुल्ला ने 'द वायर' के लिए पत्रकार करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ''मैंने इसके लिए अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक साख दांव पर लगा दी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने इसका एक बड़ा हिस्सा खो दिया है।'' उन्होंने कहा, ''मैं उन गुनाहों की सजा भुगतूंगा जो मेरे नहीं हैं, और मैं फिर से वह सलीब उठाऊंगा ज़्योंकि उसे उठाना मेरी ही जिज़्मेदारी है।'' जज़्मू-कश्मीर को सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने की केंद्र की अस्पष्ट समय-सीमा की आलोचना करते हुए मुज़्यमंत्री ने इस प्रक्रिया की तुलना ऐसे लक्ष्य से की, जो लगातार आगे खिसकता जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''यह मैराथन दौड़ की तरह है। इसे 42 किलोमीटर में पूरा करने के बजाय, जब भी आप अंतिम रेखा के करीब पहुंचते हैं, वे उसे आगे खिसका देते हैं।'' उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट मानदंड तय करने का आग्रह किया, ताकि उनकी सरकार के पास एक निश्चित लक्ष्य हो। अज़्दुल्ला ने इस तर्क को भी खारिज किया कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे सुरक्षा तंत्र पर उनकी निर्वाचित सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, ''इस तर्क के साथ समस्या यह है कि आप वास्तव में ऐसी सरकार को सजा दे रहे हैं, जिसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जज़्मू-कश्मीर में आतंकवाद इसलिए नहीं है कि वहां निर्वाचित सरकार है।

वास्तव में जज़्मू-कश्मीर में इस समय जो आतंकवाद रोधी तंत्र काम कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।'' उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कहकर ''आप वास्तव में यह कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देगा, तब आप राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। यानी आप यह फैसला हमारे देश की राजधानी से हटाकर इस्लामाबाद को सौंप रहे हैं।'' प्रशासनिक कामकाज में आ रही बाधाओं को रेखांकित करते हुए अज़्दुल्ला ने विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश को ''विसंगति'' बताया। उन्होंने कहा कि जज़्मू-कश्मीर ऊर्जा विकास निगम और शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थान अब भी उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं।

उन्होंने कहा, ''विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश से खराब शासन व्यवस्था का कोई और रूप नहीं हो सकता। कृपया केंद्र शासित प्रदेश रखें, लेकिन उन्हें विधानसभा न दें।'' उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल के पास अपने प्रशासनिक सचिवों का चयन करने या महाधिवक्ता की नियुक्ति करने तक का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 पर अपना रुख कमजोर करने के आरोपों का जवाब देते हुए अज़्दुल्ला ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों के किसी भी विभाजन के लिए राज्य का दर्जा एक पूर्व कानूनी शर्त है।

उन्होंने कहा, ''अनुच्छेद 370 मूल रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा था। जब आप राज्य ही नहीं हैं तो राज्य सूची कैसे हो सकती है? अनुच्छेद 370 की बहाली से पहले राज्य का दर्जा बहाल होना जरूरी है।'' केंद्र सरकार के वादे पर अज़्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्र के अपने दौरों के दौरान व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

विविध समाचार

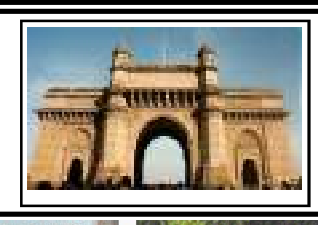

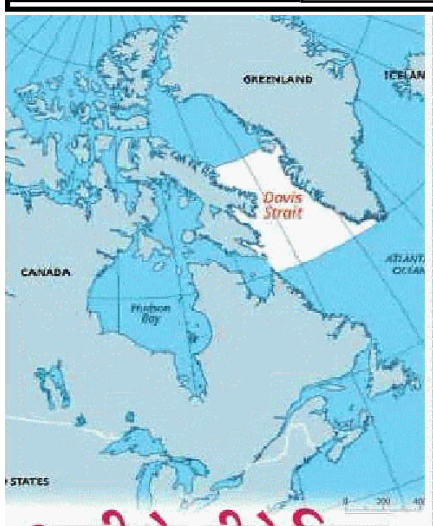

धरती के नीचे मिला करोड़ों साल पुराना रहस्यमयी महाद्वीप

वैज्ञानिकों की यह खोज बदल सकती है पृथ्वी का भूगोल!

धरती पर एक से बढ़कर एक द्वीप और महाद्वीप है, जो अपने अनोखे और अलग-अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कुछ विश्व प्रसिद्ध द्वीप है, तो कुछ के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महाद्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि करोड़ों साल पुराना है। जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर कुल सात महाद्वीप है। जिनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है।

डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रोकॉन्टिनेंट

लेकिन आज हम आपको जिस महाद्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा है। यह काफी हैरान करने वाली खोज है। आपने ग्रीनलैंड का नाम सुना ही होगा, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने यहां मोटी बर्फ की चादर के नीचे रहस्यमई महाद्वीप की खोज की है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस स्ट्रेट में पाया गया है। इस खोज ने भूगोल की दुनिया में खलबली मचा दी है। लोग इसके बारे में सुनकर बिल्कुल हैरान है। इस नए महाद्वीप को डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रोकॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। इसके बारे में अभी भी खोजबीन जारी है।

वैज्ञानिकों का यह है मानना

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह महाद्वीप का एक टुकड़ा है, जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया और समुद्र तल के नीचे दब गया। उनके मुताबिक, यह 58 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की मानें तो यह घटना ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की टैक्टोनिक प्लेट्स अलग होने के दौरान की है। उस दौरान संभवत: यह स्थान समुद्र की गहराई में बर्फ की चादर के नीचे जाकर दब गया हो। इतने सालों बाद वैज्ञानिकों की इस नई और रहस्यमई खोज को वाकई अद्भुत मानी जा रही है।

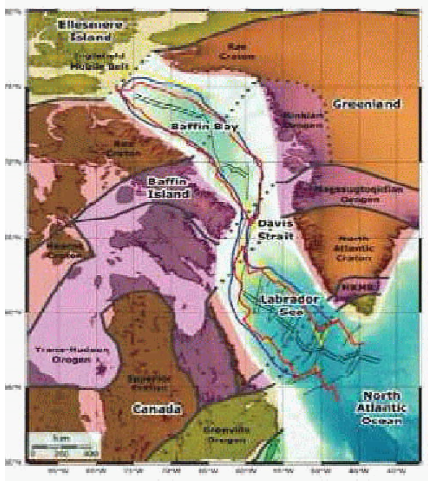

1724 में क्यों बनवाया गया था दिल्ली का जंतर-मंतर?

विज्ञान का चमत्कार है इसका रहस्य

दिल्ली का जंतर-मंतर 300 साल पहले आकाश में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की सही स्थिति जानने के लिए बनवाया था। आइए जानते हैं कि आखिर जंतर-मंतर में कौन-कौन से खास यंत्र हैं। दिल्ली का जंतर-मंतर लगातर चर्चा में बना हुआ है। हाल के दिनों में यहां बड़े प्रदर्शन और धरनों की वजह से यह जगह लगातार सुर्खियों में रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिस जगह को लोग विरोध-प्रदर्शन के लिए पहचानते हैं, उसका असली मकसद कुछ और था।

करीब 300 साल पहले इसे न तो धरना न देने के लिए बनाया गया था और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए। 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे आकाश में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की सही स्थिति जानने के लिए बनवाया था। उस समय यह अपने दौर का बहुत ही मॉडर्न साइंटिफिक सेंटर हुआ करता था। यहां के बड़े यंत्र बिना बिजली और मशीन के समय बताते थे। साथ ही आकाश और तारों के बारे में हिसाब-किताब लगाने में मदद करते थे। आइए इसके बारे में जानते हैं सब कुछ-

जंतर-मंतर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी

जंतर-मंतर को 1724 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। उन्हें एस्ट्रोनॉमी में खास रुचि थी। उस समय इस्तेमाल होने वाले छोटे औजारों से सही हिसाब लगाना मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने बड़े-बड़े यंत्र (मशीनें) बनवाए ताकि बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। जंतर-मंतर नाम भी इसी काम से जुड़ा है। इसमें जंतर का मतलब है मशीन या औजार और मंतर का मतलब है हिसाब-किताब या फॉर्मूला। यानी जंतर-मंतर एक ऐसी जगह है, जहां मशीनों की मदद से ग्रहों और तारों का हिसाब लगाया जाता था।

दिल्ली का जंतर-मंतर था पांच वेधशालाओं में सबसे पहला

दिल्ली का जंतर-मंतर राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे पहला था। इसके बाद उन्होंने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी ऐसी ही जगहें बनवाई। इन सभी को बनाने का मकसद एक ही था कि सूरज, चांद और तारों की चाल को समझना और सही समय व मौसम का सटीक हिसाब लगाना। इनमें से जयपुर का जंतर-मंतर सबसे बड़ा है। आज हमारे पास टेलीस्कोप और कंप्यूटर हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट नंगी आंखों से ग्रहों और तारों की स्थिति का अध्ययन करते थे। दिल्ली के जंतर-मंतर में बने बड़े-बड़े यंत्र इसी काम के लिए तैयार किए गए थे। यहां बने 13 यंत्र सूरज, चांद और ग्रहों की जगह देखने और उनके बारे में सही हिसाब-किताब लगाने में मदद करते थे।

सम्राट यंत्र: विशाल सूर्य घड़ी

जंतर-मंतर का सबसे प्रसिद्ध यंत्र सम्राट यंत्र है। यह एक बड़ी सी सूर्य घड़ी (संडायल) है। इसे पृथ्वी की धुरी के समान बनाया गया है। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो उसकी छाया देखकर समय का पता लगाया जाता था। अपने समय में यह काफी सटीक माना जाता था।

राम यंत्र का क्या काम था

जंतर-मंतर में दो बड़े गोलाकार खुले ढांचे बने हुए हैं, जिन्हें राम यंत्र कहा जाता है। इनका इस्तेमाल आसमान में दिखाई देने वाले ग्रहों और तारों की ऊंचाई और उनकी स्थिति मापने के लिए किया जाता था।

जय प्रकाश यंत्र क्यों है खास

जंतर-मंतर का 'जय प्रकाश यंत्र' बहुत खास है। इसे कटोरी (आधे गोले) जैसे दो बड़े डिजाइन में बनाया गया है। इसकी मदद से आसमान में तारों और ग्रहों की सही जगह पता की जाती थी।

मिश्र यंत्र का था यह काम

जंतर-मंतर का एक और खास यंत्र है, जिसे मिश्र यंत्र कहा जाता है। यह पांच अलग-अलग यंत्रों का मिला-जुला ही रूप है। इसकी मदद से साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन की जानकारी ली जाती थी।

ईंट, पत्थर और चूने से बने हैं ये विशाल यंत्र

आपको बता दें कि जंतर-मंतर के ज्यादातर यंत्र ईंट, पत्थर और मलबे से बनाए गए हैं। इनके ऊपर चूने का प्लास्टर किया गया है। समय के साथ इनकी मरम्मत भी की जाती रही है ताकि ये सुरक्षित रहें।

आज पहले जैसी सटीक गणना क्यों नहीं हो पाती

जब जंतर-मंतर बनाया गया था तब इसके आसपास खुला इलाका था। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थीं। ऐसे में इससे सूरज और आसमान साफ दिखाई देते थे, लेकिन अब इसके चारों तरफ ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। इसी वजह से पहले जैसी सटीक जानकारी हासिल करना संभव नहीं है।

वैज्ञानिकों के साथ आर्किटेक्ट भी करते हैं इसकी तारीफ

वैज्ञानिकों के साथ-साथ इमारतें बनाने वाले (आर्किटेक्ट) भी इसकी तारीफ करते हैं। जंतर-मंतर सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन बनावट के लिए भी जाना जाता है। इसके बड़े-बड़े यंत्र और इसका शेप दुनिया भर के डिजाइनरों, इतिहासकारों और कला के जानकारों को बहुत पसंद आते हैं। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे खास और अनोखी ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है।

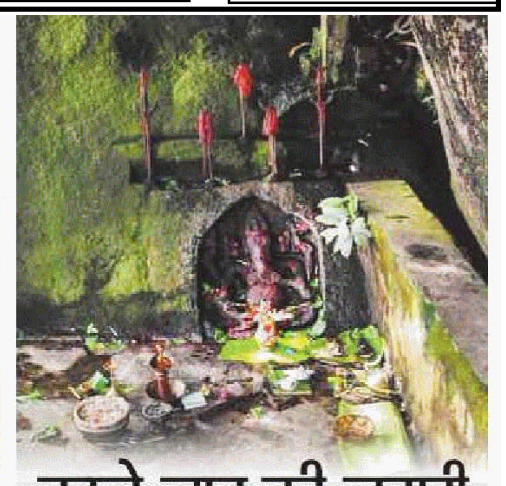

काले जादू की नगरी कही जाती है यह जगह, जानें इसके पीछे की कहानी

क्या आप भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी गांव के बारे में जानते हैं? असम का मयोंग गांव सदियों से काले जादू की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां के स्थानीय लोग तंत्र-मंत्र से लाइलाज बीमारियों को ठीक करते हैं। मोरीगांव जिले की रहने वाली हंसिका से जानते हैं यहां की कहानी।

भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं, जिनका इतिहास और कहानियां आज के विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। इन्हीं में से एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी जगह है असम का मयोंग गांव, जिसे सदियों से काले जादू की राजधानी या ब्लैक मैजिक का गढ़ कहा जाता है। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा यह गांव अपनी खूबसूरती के साथ-साथ सदियों पुराने तंत्र-मंत्र, तंत्र विद्या और काले जादू के रहस्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मयोंग का नाम सुनते ही आज भी लोगों के जेहन में एक अजीब सा खौफ और उत्सुकता जाग उठती है। आज हम आपको स्थानीय निवासी इस जादुई नगरी और इसके पीछे के रहस्यों के बारे में क्या दावों और कहानियों का जिक्र करते हैं।

मयोंग को कहा जाता है कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक जब मुगल लोग असम को इन बिल्ड करने आए थे और वह मयोंग गांव की तरह गए थे, तब वहां के लोगों ने अपने जादू और तंत्र-मंत्र से 3 लोगों को गायब कर दिया था। इसकी जानकारी मोरीगांव में रहने वाली हंसिका ने बताई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इसकी कहानी महाभारत से भी जुड़ी है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां के लोग इतने जानकार और इंटेलेक्चुअल थे कि वह मंत्रों का वैज्ञानिक तरीके से बीमारी को सही करने में इस्तेमाल करते थे। अभी भी वहां पर जो मंत्र-तंत्र यूज किया जाता है वह पॉजीटिव तरीके से किया जाता है।

वर्तमान में कैसा है मयोंग?

आज भी मयोंग के लगभग हर घर में तंत्र-मंत्र और काले जादू की सदियों पुरानी पांडुलिपियां मौजूद हैं। हालांकि, वक्त के साथ कई बेशकीमती कॉपियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन आज भी 'मयोंग सेंट्रल म्यूजियम' में जादू-टोने से जुड़ी कई प्राचीन लिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। आज भी मयोंग के ग्रामीण इलाकों में तांत्रिक मंत्रों के जरिए गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं।

सुंदर पर जानलेवा है यह फूल

हमारे आस-पास तमाम ऐसे पेड़-पौधे मौजूद होते हैं, जिनकी पत्तियां और उन पर खिलने वाले फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। इन्हीं में से कुछ फूल ऐसे होते हैं, जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन असल में वह खतरनाक होते हैं। यहां हम एक ऐसे रंग-बिरंगे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं।

लैंटाना कमारा : दिखने में खूबसूरत, असल में है खतरनाक

फूल हर किसी को पसंद होते हैं। हमारी प्रकृति में तमाम सारे ऐसे पेड़-पौधे मौजूद हैं, जिनकी बनावट और उस पर खिलने वाले फूल लोगों को अपनी आकर्षित करते हैं। मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सुंदर दिखने वाली चीज हमेशा वैसी ही हो। यह लाइन लैंटाना कमारा फूल पर बिल्कुल सटीक बैठती है।

रंग-बिरंग दिखने वाले ये फूल जंगलों, सड़कों के किनारे या खाली मैदानों में गुच्छे झाड़ियों पर खिले दिखाई देते हैं। ये फूल दिखने में जितने मनमोहक और मासूम लगते हैं, असल में इनका पौधा उतना ही आक्रामक और जहरीला होता है। आज हम आपको इस फूल के खतरनाक होने के पीछे के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं।

इस फूल का नाम क्या है

कई रंगों में मौजूद इस फूल का नाम लैंटाना कमारा है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे स्थानीय तौर पर रायमुनिया, घनेरी या पंचरंगी के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके एक ही गुच्छे में आपको पीले, नारंगी, लाल, गुलाबी और बैंगनी जैसे कई रंग एक साथ देखने को मिल जाते हैं।

क्यों कहा जाता है खतरनाक

लैंटाना कमारा के पौधा पर खिलने वाले रंग-बिरंगे फूल और पत्तियां दिखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन यह इंसानों, मवेशियों और हमारी धरती की जैव विविधता के लिए खतरा है। इस पौधे की पत्तियों और इसके कच्चे फलों में लैंटैडीन ए और लैंटैडीन बी नाम के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जो जहरीले तत्व हैं।

भारत में कहां से आया

लैंटाना कमारा पौधा दक्षिण और मध्य अमेरिका से आया विदेशी पौधा है। अंग्रेजों ने 1807 में इसे सजावटी पौधे के रूप में कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में लगाया था। इसके रंग-बिरंगे फूलों के कारण इसे बगीचों में खूब लगाया गया, लेकिन यह तेजी से फैलने वाला खरपतवार बन गया। ये आपको भारत के जंगलों, सड़कों के किनारे और बंजर जमीन पर उगे हुए आसानी से देखने को मिल सकते हैं।

पर्यावरण के लिए दुश्मन

लैंटाना कमारा पौधा जहरीला होने के साथ-साथ आक्रामक प्रजाति है। यह पौधा बहुत तेजी से फैलता है और आसपास के अन्य उपयोगी पौधों, घासों और लोकल वनस्पतियों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसकी जड़ों से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो दूसरी घासों को उगने नहीं देते। इसके कारण जंगलों में शाकाहारी जीवों के लिए चारे की कमी हो जाती है और जानवर जंगल छोड़ बाहर आने के लिए मजबूर हो गए हैं।

कलिंग समाचार

रविवार 09 अगस्त 2026

लोकतंत्र के लिए खतरनाक पक्षपाती रवैया

राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जो सत्तापक्ष को इतने आपत्तिजनक लगे कि राहुल गांधी से माफी की मांग की जाने लगी। एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बार-बार स्थगित हुई, क्योंकि विपक्षी सांसदों के बयान सत्तापक्ष को मंजूर नहीं थे। हंगामे के बीच पेपर लीक विरोधी विधेयक तो लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। किंतु लोकसभा में केवल सत्तापक्ष की ध्वनि के लिए जगह बची है, यह बात फिर स्थापित हो गई। 2024 में जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, भाजपा सरकार पहले से ज्यादा उद्वेलित और असहज दिखने लगी है। राहुल गांधी ने कहा ही था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में उनका सामना करने की हि मत नहीं है, इसलिए वे सदन में नहीं आते। अब शायद यही बात गृहमंत्री अमित शाह पर भी लागू हो जाएगी। उनका भाषण पूरा नहीं हो पाया, कई बार उन्हें टोका गया। जिस पर राहुल गांधी को यहां तक कहना पड़ा कि अगर इस सदन में केवल भाजपा को बोलने का अधिकार है, तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं। हमेशा की तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला फिर निष्पक्ष रवैया दिखाने में नाकाम रहे। वे भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष कहकर अपनी बात रख रहे हों, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के लिए मान उनके व्यवहार में नजर नहीं आया। यही बात सत्तापक्ष के सभी सांसदों पर लागू होती है। खासकर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू पर, जिनका एकमात्र काम इस समय मोदी-शाह का बचाव करना नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने पेपर लीक आंदोलन में उतरे छात्रों पर गोलियां चलाने के लिए अमित शाह को जि मेदार ठहराया। जिस पर सत्तापक्ष भड़क उठा। किरण रिजीजू ने कहा कि इस बात के सबूत दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो फिर ऐसा कहना ठीक नहीं है, आप माफी मांगिए। रिजीजू ने यह भी कहा कि ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया है। क्या ऐसा कहना ठीक होगा। बात सही है कि सदन में किसी का भी नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी किसी की भी बात नहीं कर रहे थे, वे बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह की बात कर रहे थे, जिनके अधीन पुलिस प्रशासन आता है, जिनके जि मे देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है। जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठी और आंसू गैस के गोले के अलावा पैलेट गन से वार किया गया, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें लगने की खबरें हैं। एक छात्र को तो राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने दिखाया भी था, जिसकी आंख फूटने का खतरा बना हुआ है। एक पत्रकार को भी पैलेट गन से चोट लगी है। इसी तरह बिहार में पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल के हाथों में एके 47 लेकर छात्रों की तरफ निशाना साधे दिखे हैं, उसके वीडियो सामने हैं, इसी आधार पर उन्हें निलंबित भी किया गया है। तो क्या यह सवाल अमित शाह से नहीं किया जाएगा कि क्या उन्होंने छात्रों के खिलाफ बंदूकें तानने के आदेश दिया, गोली चलाने के आदेश दिए। अगर नहीं दिए और फिर भी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो यह ज्यादा गंभीर बात है कि पुलिस गृहमंत्री को अंधेरे में रखकर काम कर रही है। दोनों ही सूरतों में जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस समय भाजपा सरकार देश को अंधेरे में रखने का ही काम कर रही है। छात्रों पर पुलिसिया ज्यादती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्या सरकार वहां जवाब नहीं देगी। अगर कानूनी अदालत में सरकार बोल सकती है, तो फिर जनता के चुने प्रतिनिधि जब यही सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब देने से क्यों बच रही है। अगर अमित शाह संसद आते और राहुल गांधी को आमने-सामने जवाब देते तो हंगामा होता ही नहीं। लेकिन भाजपा की रणनीति यही है कि हंगामे की आड़ में जवाबदेही से बचा जाए। संसद के बजट सत्र में भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया था, क्योंकि वे चीन से सीमा विवाद पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को उद्धृत करना चाहते थे। राहुल के भाषण में कई बार व्यवधान उत्पन्न किया गया और उन्हें आखिरकार पूरी बात कहने से रोका गया। इससे पहले शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर इसी तरह विपक्ष की बात उठने नहीं दी गई। इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनकी सांसदी बनी हुई है।

बाह्य ऋण, विकास और वैश्विक जिमेदारी

अरुण डनायक

हाल के समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाज़ार से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति के चलते बाह्य ऋण पर निर्भरता बढ़ने की संभावना बनी है, जिससे कंपनियों के लिए विनिमय-दर जोखिम का प्रबंधन और अधिक जटिल तथा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत का बाह्य ऋ ण संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाह्य ऋण किसी भी राष्ट्र के लिए एक अपरिहार्य यथार्थ बन चुका है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। मध्य-आय जाल की स्थिति में विकास की गति बनाए रखने, अवसंरचना, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में निवेश तथा विशाल जनसं या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य पूंजी की आवश्यकता बनी रहती है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने बाह्य उधारी को अंधानुकरण नहीं, बल्कि एक सुविचारित नीति-उपकरण के रूप में अपनाया है। इसका उपयोग मु यतः अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक विस्तार और वित्तीय स्थिरता के लिए किया गया है। विशेष रूप से, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और आवश्यकता पड़ने पर आईएमएफ से प्राप्त ऋणों ने निजी क्षेत्र को भुगतान-संतुलन बनाए रखने में सहायता दी, जिससे निवेश, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन को बल मिला। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी ऋण लेने की सीमित संभावना होती है, और अधिकांश बाह्य उधारी केंद्र सरकार के माध्यम से होती है , जिससे ऋ ण प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को संस्थागत रूप से नियंत्रित रखा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, जून 2025 के अंत तक केंद्र और राज्यों का कुल बाह्य ऋ ण 747.2 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2025 में हल्का घटकर लगभग 746 अरब डॉलर रह गया—अर्थात समग्र स्तर पर स्थिरता बनी रही। यह जून 2024 के 681.5 अरब डॉलर की तुलना में वार्षिक आधार पर 9.6 प्रतिशत अधिक है।

दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के माध्यम से उधारी प्रवाह में वृद्धि के संकेत मिले; दिसंबर माह में अकेले 4.43 अरब डॉलर की नई ईसीबी जुटाई गई, जिससे अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान कुल जुटाई गई राशि लगभग 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह आंकड़े प्रवाह को दर्शाते हैं, न कि कुल बकाया स्टॉक को। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं।

ऋण राशि बढ़ने के बावजूद बाह्य ऋण-से-जीडीपी अनुपात मार्च 2025 के 19.1 प्रतिशत से घटकर 18.9 प्रतिशत रह गया है, जो दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि ऋण वृद्धि से तेज़ रही। यद्यपि केंद्रीय सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों (रुपए 34.96 लाख करोड़) की तुलना में बाह्य ऋण का स्तर ऊंचा प्रतीत होता है, फिर भी यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अभी जोखिम की सीमा के भीतर है। हाल के समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाज़ार से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति के चलते बाह्य ऋण पर निर्भरता बढ़ने की संभावना बनी है, जिससे कंपनियों के लिए विनिमय-दर जोखिम का प्रबंधन और अधिक जटिल तथा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत का बाह्य ऋ ण संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। 82 प्रतिशत दीर्घकालिक, अल्पकालिक मात्र 18.1प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार से 93प्रतिशत से अधिक आच्छादन, ऋण-सेवा अनुपात के वल 6.6प्रतिशत तथा परिसंपत्ति-दायित्व अनुपात 79.25प्रतिशत होने के कारण तात्कालिक जोखिम न्यूनतम है। यद्यपि डॉलर पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता से विनिमय-दर जोखिम उत्पन्न होता है, लेकिन लगभग 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा 93 प्रतिशत से अधिक बाह्य ऋ ण का आच्छादन इस जोखिम को प्रभावी रूप से संतुलित करता है। रुपये की डॉलर के मुकाबले हाल की कमजोरी का असर सीधे कुल बाह्य ऋण की राशि पर नहीं पड़ता। इसका मु य प्रभाव ऋण-सेवा लागत, ब्याज भुगतान और भविष्य में ऋण के पुनर्भुगतान पर पड़ता है, जिससे कंपनियों और सरकार की वित्तीय योजना पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।

आम धारणा के विपरीत, भारत का बाह्य ऋण किसी एक देश या संस्था पर केंद्रित नहीं है। इसका स्वरूप विविध और संतुलित है— 40 प्रतिशत वाणिज्यिक उधारी (अंतरराष्ट्रीय बांड और विदेशी बैंक), 22 प्रतिशत एनआरआई जमाएं, 11 प्रतिशत विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं, 5 प्रतिशत जापान जैसे द्विपक्षीय ऋणदाताओं, तथा आईएमएफ की 21.6 अरब डॉलर की सीमित देनदारियां (मु यतः 1991 के संकट से जुड़ी)। भारत ने वर्षों से आईएमएफ से कोई नया कार्यक्रम ऋण नहीं लिया, जिससे नीति-स्वायत्तता बनी रही। भारत की ऋण-चुकाने की क्षमता लगातार मज़बूत बनी हुई है।

मूलधन और ब्याज सहित ऋण-सेवा भुगतान चालू प्राप्तियों का केवल 6.6 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां-दायित्व अनुपात 79.25 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, अर्थात भारत की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां उसकी कुल विदेशी देनदारियों के लगभग 80प्रतिशत को आच्छादित करती हैं। यह भारत की बाह्य भुगतान क्षमता की मजबूती और तात्कालिक बाह्य संकट से सुरक्षा को स्पष्ट करता है। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बाह्य ऋण प्रबंधन की जटिलता बढ़ा सकती हैं, विशेषकर वाणिज्यिक उधारी में, जहां सतत निगरानी और विवेकपूर्ण नीति आवश्यक है। फरवरी 2026 में आरबीआई ने ईसीबी ढांचे में उदारीकरण करते हुए पात्र उधारकर्ताओं की श्रेणी का विस्तार, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत कुछ सीमाओं में शिथिलता, औसत परिपक्वता अवधि संबंधी शर्तों में लचीलापन तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया। इससे भारतीय कंपनियों—विशेषकर अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र—के लिए विदेशी पूंजी जुटाना अधिक सुगम होगा। बाह्य ऋण प्रबंधन के साथ-साथ भारत आज 65 से अधिक देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला एक प्रमुख राष्ट्र है। भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरीशस, यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा अनेक अफ्रीकी देश प्रमुख सहयोग प्राप्त देश हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत लगभग रुपए 6,750 करोड़ विदेशी सहायता के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारत न तो ग्रीस और अर्जेंटीना जैसी गंभीर ऋण-जाल वाली अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में है, जहां वित्तीय अनुशासन की कमी, उच्च सार्वजनिक ऋण और संरचनात्मक कमजोरियां संकट का कारण बनी थीं और न ही 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से प्रभावित देशों जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। थाईलैंड में संकट अल्पकालिक ऋण और भुगतान असंतुलन से, इंडोनेशिया में विदेशी ऋण और अवमूल्यन से, तथा दक्षिण कोरिया में अत्यधिक देनदारियां और बैंकिंग संकट से उत्पन्न हुआ था। इसके विपरीत, भारत ने दीर्घकालिक ऋण संरचना, संतुलित मुद्रा संयोजन, मजबूत बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई के कठोर पर्यवेक्षण तथा ऋण चुकाने की प्रतिबद्धता के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखी है। भारत अवसंरचना, उद्योग और रोजगार सृजन के लिए विवेकपूर्ण उधारी करता है और विगत सरकारों द्वारा अपनाई नीतियां आज भी बाह्य ऋण प्रबंधन को मजबूत रखती हैं और दीर्घकालिक निवेश, सतत विकास तथा पड़ोसी सहायता में नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करती हैं। उधार और उदारता की रणनीति भारत की आर्थिक परिपक्वता, वित्तीय अनुशासन और अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व को दर्शाती है, जबकि वैश्विक ब्याज दरों, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और संरक्षणवाद के मद्देनज़र सतत निगरानी की आवश्यकता बनी हुई है।

यह प्रधानमंत्री की शर्मिंदगी नहीं, बौखलाहट है

अनिल जैन

दरअसल मोदी के लिए लोकतंत्र का मतलब महज किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्ता, विपक्ष से संवाद और सरकार से असहमति आदि के लिए उनके लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। इसलिए वे अपनी सरकार के खिलाफ़ उठने वाली हर आवाज को देशविरोधी करार देने में कोई देरी या संकोच नहीं करते। इसकी वजह यह भी है कि उनकी राजनीतिक परवरिश लोकतांत्रिक माहौल में नहीं बल्कि एकचालकानुवर्तित्व के माहौल में हुई है। उन्होंने सत्ता में आने से पहले के अपने राजनीतिक जीवन में सरकारविरोधी किसी आंदोलन में शिरकत नहीं की और जेल जाना तो दूर, किसी पुलिस थाने का मुंह तक नहीं देखा। इसलिए उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपनी सरकार का विरोध बेहद अटपटा लगता है और वे बौखला जाते हैं।

मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अधिकांश देशों की यात्राएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री और गुजरात का मु यमंत्री बनने से पहले भी आधुनिक विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका की यात्रा तो उन्होंने कई बार की है, जैसा कि वे खुद कई मर्तबा बतला चुके हैं। इसके बावजूद वे इस तथ्य से अनजान हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान किसी मुद्दे को लेकर विरोध-प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के मौके पर वहां के राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र या मानवाधिकार संस्थाएं किसी मुद्दे को लेकर विरोध और प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन वहां विरोध करने वालों को देशद्रोही कहना तो दूर गिर तार भी नहीं किया जाता है। मोदी ने खुद भी प्रधानमंत्री के नाते ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शिरकत की है और कुछ आयोजनों के दौरान तो वहां मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं।

हमारे ही देश में पहले कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के मौके पर ऐसे विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के खिलाफ़ लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था और फिर छोड़ दिया था। किसी ने उन्हें देशद्रोही या लोकदल के नेता चौधरी चरणसिंह को %नंगा% नहीं कहा था। उसके बाद दिल्ली में ही 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर स मेलन हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। उस आयोजन के मौके पर लोकदल और वामपंथी दलों ने कुछ ही समय पहले असम में हुए शर्मनाक नेल्ली नरसंहार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही नहीं कहा था और न ही देश की छवि खराब होने का राग अलापा था। दिल्ली में ही 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गे स के मौके पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था। तब भी किसी ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही नहीं कहा और न ही किसी को गिर तार किया। बहरहाल एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन रणनीतिक रूप से सही था या गलत, इस पर तो बहस हो सकती है मगर इसमें शर्मसार होने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री और उनके तमाम सहयोगी नाराज़ हुए जा रहे हैं। जबकि एआई समिट के दौरान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के अलावा ऐसी कई बातें हुई हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं हो रहे हैं। आयोजन के पहले दिन प्रधानमंत्री के फोटो सेशन के लिए आयोजन स्थल को पांच घंटे के लिए पूरी तरह खाली करा लिया गया था, जिससे विदेशी मेहमानों को काफी परेशानी हुई और उस दौरान कई विदेशी मेहमानों के कीमती सामान चोरी हो गये परन्तु इस पर किसी को शर्म नहीं आ रही है।

एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन में बने रोबोटिक डॉग को अपने यहां निर्मित हुआ बताते हुए उसका प्रदर्शन किया। यही नहीं, उस चीनी रोबोटिक डॉग को भारत सरकार के सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भारतीय आविष्कार और प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम बताया, जिससे दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई, लेकिन मोदी सहित किसी को भी शर्म ने छुआ तक नहीं। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को टॉप यूनिवर्सिटी के अवार्ड से नवाजा था। वैसे एआई समिट के अलावा भी पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में ऐसे कई वाकये हुए हैं जिनसे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है लेकिन किसी को शर्म नहीं आई- न प्रधानमंत्री को, न उनकी सरकार व पार्टी को और न ही मु यधारा के मीडिया को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र प अपने देश के मीडिया के समक्ष कहते हैं, %मैं प्रधानमंत्री मोदी का कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, इसलिए मुझे खुश करना मोदी की मजबूरी है।% संप्रभुता संपन्नता भारत को अपमानित करने वाले इस बयान पर किसी को शर्म नहीं आती। यही नहीं, ट्रंप ने 50 से अधिक बार कहा है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को धमका कर उनके बीच सीज़फायर करवाया। ट्र प के इस दावे पर किसी का जमीर नहीं जागता। ज़्यादा जानें तकनीकी समाचार बुलेटिन ई-पेपर सब्सक्रिप्शन हिंदी समाचार सदस्यता सुदूर पूर्वोत्तर के मणिपुर में जब एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाते हैं, जिसकी खबरें दुनिया भर के मीडिया में प्रमुखता से जगह पाती हैं, तब भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को शर्म नहीं आती है। देश में हिंदू राष्ट्र और सनातन का राग अलापने वाले महंत और महामंडलेश्वर जब यौन दुराचार के मामलों में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तब भी किसी को शर्म नहीं आती। उस समय भी किसी को शर्म नहीं आती जब बलात्कार के सज़ाया ता लोगों की सज़ा माफ कर दी जाती है और उनके जेल से रिहा होने पर हार-फूलों से उनका स्वागत किया किया जाता है। भारत की छवि तब भी खराब नहीं होती है जब देश की उच्च अदालतें बलात्कार जैसे वीभत्सतम अपराध की उलजुलूल व्या या करते हुए बलात्कारियों की हौसला अफजाई करती हैं, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती। जब भाजपा शासित उत्तराखंड में 20 साल की एक युवती को सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली नेता अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर देते हैं, तब भी किसी को शर्म नहीं आती है। शर्मसार होने से जैसे और भी कई मामले हैं और संचार क्रांति के दौर में उनकी जानकारी दुनिया भर को है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उनसे बेखबर रहती है। अमेरिका के कु यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की फाइलों में नाम आने पर दुनिया भर में कई सत्तारूढ़ नेताओं और उच्च अधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। उन फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रियों और उनके दोस्त उद्योगपतियों का भी नाम आना तथा सरकार के एक मंत्री के एपस्टीन से करीबी संबंधों का खुलासा हो जाना पूरे देश के लिए शर्म की बात है, पर सरकार, सत्तारूढ़ दल और मीडिया के स्तर पर शर्म का कोई अता-पता नहीं है। इन सभी को शर्म आती है तो सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि चमकाने की कवायद के तहत हुए एआई समिट में प्रमुख विपक्षी पार्टी के 12 कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर। मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, %लोकतंत्र में ऐसा मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो सरकार को तलवार की धार पर चलने के लिए मजबूर कर दे। मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही बात का अफसोस है कि मुझे मजबूत विपक्ष नहीं मिला, इससे मेरा दिल दुखता है। उस चुनाव में व्यापक पैमाने पर हुई गड़बड़ियों और चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये के बावजूद चुनाव परिणामों से प्रधानमंत्री की इच्छा पूरी हुई। उन्हें एक मजबूत विपक्ष मिला लेकिन अफसोस है कि वह विपक्ष प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रहा है।

विविध समाचार

बठिंडा में भीषण सड़क हादसा : अमरनाथ यात्रियों से भरा टेंपो ट्रैवलर ट्राला से टकराया, 4 की मौत–8 घायल

बठिंडा। पंजाब के बठिंडा–बीकानेर नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर की सड़क किनारे खड़े ट्राला से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो ट्रैवलर का अगला हिस्सा करीब 3 से 4 फीट तक पिचक गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया।

सभी घायलों को तत्काल बठिंडा स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार, राजस्थान से 11 से 12 श्रद्धालु टेंपो ट्रैवलर में सवार होकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे। बुधवार सुबह करीब 7 बजे जब वाहन बठिंडा के डाबा जोर गांव, जोधपुर रोमाना और गुरुसर सानेवाला के बीच पहुंचा, तभी सड़क किनारे खड़े एक ट्राला से पीछे से जा टकराया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन में फंसे यात्रियों की चीख–पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। सहारा जन सेवा संस्था के कार्यकर्ता संदीप सिंह ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम से हादसे की सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल अधिकारी डॉ. लवदीप सिंह ने बताया कि सहारा जन सेवा संस्था द्वारा लाए गए घायलों में तीन लोगों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया, जबकि एक अन्य घायल की मौत एम्स ले जाते समय हो गई।

सभी घायल यात्रियों का इलाज एम्स बठिंडा में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सड़क किनारे खड़े ट्राला से टकराने को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है।

मोदी सरकार जल्द दिलाएगी करतारपुर, फिल्लौर और आदमपुर के लोगों को बंद रेलवे फाटकों से राहत

जालंधर। विधानसभा करतारपुर और फिल्लौर से पूर्व विधायक पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अविनाश चंद्र कलेर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से मुलाकात कर फिल्लौर, करतारपुर और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख रेलवे फाटकों पर अंडरब्रिज एवं ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर विस्तृत लिखित आवेदन सौंपा। कलेर ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में लंबे समय से बंद रहने वाले रेलवे फाटकों के कारण लोगों को प्रतिदिन भारी जाम, समय की बर्बादी और आपातकालीन परिस्थितियों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि विधिापुर, गोराया, फिल्लौर स्थित बाबा साहिब अंबेडकर चौक के समीप रेलवे फाटक, फिल्लौर–बिलगा रेलवे फाटक तथा आदमपुर विधानसभा के खुर्द सहित अन्य प्रमुख रेलवे फाटकों पर प्राथमिकता के आधार पर अंडरब्रिज एवं ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कलेर को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार आम जनता की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रेल मंत्रालय इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाएगा, ताकि करतारपुर, फिल्लौर और आदमपुर के लोगों को वर्षों पुरानी रेलवे फाटक की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। अविनाश चंद्र कलेर ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार लगातार पंजाब में आधुनिक रेलवे ढांचे का विस्तार कर रही है और जनता की सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है।

पानीपत में कबाड़ी फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, कपड़े की गांठ के नीचे दबकर महिला श्रमिक की मौत

पानीपत। हरियाणा के पानीपत में थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक कबाड़ी फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला श्रमिक की मौत हो गई। फैक्ट्री में काम के दौरान कपड़े की भारी गांठ गिरने से महिला उसके नीचे दब गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी माया देवी के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ समय से फैक्ट्री में मजदूरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह अन्य श्रमिकों के साथ काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक कपड़े की भारी गांठ गिर गई और वह उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में मौजूद अन्य मजदूरों ने तत्काल माया देवी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई मोनू ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा : गहरी खाई में गिरी कार, चार लोगों की मौत

नकरोड। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा उपमंडल में नकरोड़–हिमगिरि डैम साइड सड़क पर हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ, लेकिन अंधेरा और सुनसान इलाका होने के कारण इसकी जानकारी रविवार सुबह स्थानीय लोगों को मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार नकरोड़ से हिमगिरि की ओर जा रही थी। इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। रात के समय घटना का किसी को पता नहीं चला। सुबह स्थानीय लोगों की नजर खाई में गिरे वाहन पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दुर्गम खाई में राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल मृतकों की पहचान और वाहन मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक डॉ. हंसराज भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि नकरोड़–हिमगिरि मार्ग पर हुए इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हुई है।

पंजाब में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, मावां-धीयां सत्कार योजना लॉन्च

चंडीगढ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को अपने गृह जिले धूरी से बहुप्रतीक्षित 'मुख्यमंत्री मावां–धीयां सत्कार योजना' लॉन्च की। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में तीन महीने की सम्मान राशि एकमुश्त जमा की गई। करीब 1100 करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ दिया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। पहली बार सरकार ने तीन महीने की किस्त एक साथ जारी की है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं के खातों में 3,000, जबकि SC वर्ग की महिलाओं के खातों में 4,500 जमा किए गए।

मनीमाजरा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का उद्घाटन

चंडीगढ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चंडीगढ़ अंचल के अंतर्गत आज मनीमाजरा में नई शाखा का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। शाखा का उद्घाटन हरियाणा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री प्रद्युम्न सिंह के कर–कमलों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उप अंचल प्रबंधक श्री एल. राजकिशोर पात्रो सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री प्रद्युम्न सिंह ने नई शाखा के शुभारंभ पर बैंक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं उद्यमियों को बेहतर एवं सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

उप अंचल प्रबंधक श्री

राजनीति करने नहीं दुख–दर्द बांटने आया हूँ : सीएम सुक्खू

धर्मशाला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने हेलिपैड के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग–अलग निविदाएं आमंत्रित करने तथा कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी को हवाई मार्ग से पहुंचाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ा भंगाल सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बिजली विभाग

को गांव में उपयुक्त क्षमता के डीजल जनरेटर स्थापित करने तथा सभी घरों में विद्युत कनेक्शन और वायरिंग के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए।

सड़क सुविधा उपलब्ध होने तक वैकल्पिक बिजली व्यवस्था जारी रखने का आश्वासन देते हुए उन्होंने अपर बड़ा भंगाल और लोअर बड़ा भंगाल के लिए एक–एक डीजल जनसेट उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त बाढ़ से प्रभावित जलविद्युत परियोजना को पुनः संचालित करने तथा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल के प्रसिद्ध राजमाह की अलग ब्रांडिंग कर उसे विशेष पहचान और बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय कृषि एवं बागवानी को प्रोत्साहित करते हुए लोगों से अखरोट एवं चेस्टनट के पौधे लगाने का आह्वान किया। स्थानीय मीट उत्पादों को भी बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। मोबाइल नेटवर्क सुविधा के संबंध में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई मांग पर मुख्यमंत्री ने निजी दूरसंचार कंपनियों से बातचीत कर शीघ्र मोबाइल सेवा आरंभ करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने वन भूमि का उपयुक्त क्षेत्र चिन्हित कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए तथा बड़ा भंगाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाने, छात्रावास निर्माण पर विचार करने तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने और समाप्त होने के समय हेली–टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रशिक्षित करने की बात कही, ताकि दुर्गम क्षेत्र में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनीति करने नहीं, बल्कि बड़ा भंगाल के लोगों का दुख–दर्द समझने आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति करनी होती तो वे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाते, लेकिन उनकी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे लोगों तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिमला में बैठकर योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन धरातल पर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्र का दौरा आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल को प्राकृतिक पंचायत घोषित करने, क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करने तथा राशन डिपो में खाद्यान्न कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बाढ़ से सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन वॉल निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने दो स्थानीय महिला मंडलों को दो–दो लाख रुपये तथा एक युवक मंडल को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा भी की।

नीट–यूजी और यूजीसी–नेट जैसी परीक्षाओं की तारीख निर्धारित हो : परगट सिंह

होशियारपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक परगट सिंह ने आज होशियारपुर में नीट स्कैम और पेपर लीक को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के पूरी तरह ध्वस्त होने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अपने मूल दायित्व को निभाने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण नीट–यूजी और यूजीसी–नेट जैसी कई राष्ट्रीय परीक्षाओं लीक और रद्द हुई हैं। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर विधायक परगट सिंह ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि तुरंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पेपर लीक माफिया की उनके साथ संभावित संबंधों की जांच होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए। अब कोई और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हर साल नीट–यूजी और यूजीसी–नेट जैसी परीक्षाओं और भर्ती के लिए निर्धारित सलाना कैलेंडर लागू किया जाना चाहिए। जिसमें परीक्षा की तारीखें पहले से घोषित हों और नियुक्ति की समय सीमा पहले ही घोषित की जाएं। परगट सिंह ने कहा कि सिर्फ नीट परीक्षा के लिए ही 22 लाख से अधिक परिवार मिलकर हर साल लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जबकि हमारे देश की एजुकेशन का साल का बजट 1.40 लाख करोड़ है। यानि की हर साल जितना शिक्षा पर बजट खर्च किया जाता है, उतना पैसा नीट की तैयारी में स्टूडेंट्स और उनके माता पिता का लग रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि नीट जैसी परीक्षाओं में रोजगार की गारंटी देने की बात की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर 1,000 छात्रों में से मुश्किल से 12 ही स्थायी और वेतनभोगी नौकरियां पा पाते हैं। जबकि आईआईटी के 80: स्नातकों को भी रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। परगट सिंह ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत में पेपर लीक के 89 संदिग्ध मामले सामने आए। जिनमें कम से कम 6.2 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। कम से कम 48 परीक्षाएं दोबारा करवानी पड़ी और 22 परीक्षाएं तो करवाए जाने से पहले ही रद्द हो गईं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, रविवार 09 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

लकड़ी तस्करी पर शिकंजा, लाखों की जब्ती

गंजम ०८/०८ (संवाददाता): वन विभाग ने गंजम जिले के भंजनगर में दक्षिण घुमुसर वन प्रभाग के बडागड़ा वन रेंज के तहत गंगापुर गांव के पास अवैध लकड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया और 3 लाख रुपये से ज़्यादा की लकड़ी और गाड़ी ज़ब्त की।

एक सूचना के आधार पर, वन अधिकारियों ने कीमती लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को ज़ब्त कर लिया, जिससे उसकी अवैध ढुलाई रोक दी गई। अधिकारियों के अनुसार, जानकारी मिली थी कि एक पिकअप वैन का इस्तेमाल महंगी लकड़ी की तस्करी के लिए किया जा रहा है। इसके बाद, बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने एक विशेष प्रवर्तन टीम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और संदिग्ध वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। वन विभाग की गाड़ी को देखते ही ड्राइवर पिकअप वैन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वन टीम ने गंगापुर गांव के पास लकड़ी से लदी गाड़ी को सफलतापूर्वक रोक लिया और ज़ब्त कर लिया।

ज़ब्त किए गए माल में सागौन और गंभारी की लकड़ी शामिल थी, जिन्हें कीमती वन उत्पाद माना जाता है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ऑपरेशन के दौरान कुल 46 ष्ढ्ढह्ल लकड़ी बरामद की गई।

बडागड़ा के रेंज वन अधिकारी अंजन कुमार नायक ने कहा, हमें मिली जानकारी के आधार पर, हम पिछले चार दिनों से संदिग्धों पर नज़र रख रहे थे। कल रात, हमने उन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया, और पुलिस की मदद से, हम गाड़ी का पता लगाकर उसे ज़ब्त करने में कामयाब रहे। ज़ब्त की गई लकड़ी की कीमत 70,000 रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है, जबकि गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपये से ज़्यादा है। कुल मिलाकर, ज़ब्त की गई संपज़ि की कीमत 3 लाख रुपये से ज़्यादा है।

ज़ब्त की गई पिकअप वैन और लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने बताया कि तस्करी नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

यह सफल ऑपरेशन अवैध लकड़ी व्यापार पर अंकुश लगाने और वन संसाधनों की रक्षा के लिए वन विभाग के लगातार प्रयासों को उजागर करता है। अधिकारियों ने दोहराया है कि वन संबंधी अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सज़्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करों को एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

सरकार ने 18 जिलों में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू की

भुवनेश्वर ०८/०८ (संवाददाता): नई बनी नोटिफाइड एरिया काउंसिल (ह्रष्टह्य), नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनावों की प्रक्रिया शुरू करते हुए, ओडिशा सरकार ने इस संबंध में 18 जिलों के जिला कलेज़्टरों को पत्र लिखा है। एक पत्र में, आवास और शहरी विकास विभाग ने कलेज़्टरों को मार्च तक वार्डों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शेड्यूल के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव और आपज़ियां 12 फरवरी से 21 फरवरी तक आमंत्रित की जाएंगी। परिसीमन और सीटों के आरक्षण पर नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद, 26 फरवरी से 13 मार्च तक आपज़ियां और अपील स्वीकार की जाएंगी।

स्टील मेल्टिंग शॉप-1 में इन-हाउस विकसित नए 'पाम ट्री उद्यान' का उद्घाटन

राउरकेला ०८/०८ (संवाददाता):राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपे) के स्टील मेल्टिंग शॉप-1 (एसएमएस-1) समूह की एक नई हरित पहल के अंतर्गत इन-हाउस विकसित 'पाम ट्री उद्यान' का उद्घाटन 29 जनवरी 2026 को कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बिस्वरंजन पलई द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुज़्य महाप्रबंधक (एसएमएस-1), श्री बी सुनील कार्था, कई अन्य मुज़्य महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संज़्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री पलई ने परिचालन क्षेत्र के भीतर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एसएमएस-1टीम के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और ऐसे प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, जो एक स्वस्थ एवं प्रेरणादायी कार्य वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं।

खूबसूरती से विकसित किया गया यह बगीचा एक मनमोहक हरा-भरा स्थान प्रदान करता है और पर्यावरण स्थिरता और कार्यस्थल के सौंदर्यीकरण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि यह उद्यान उस ज़मीन के एक टुकड़े पर विकसित किया गया है, जो पूर्व में अनुपयोगी एवं जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था तथा झाड़ियों और खरपतवारों से घिरा हुआ था। एसएमएस-1 कर्मीसमूह के समन्वित इन-हाउस प्रयासों से इस क्षेत्र को एक सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है, जिससे शॉप परिसर की सौंदर्यता और पर्यावरणीय गुणवज़ा दोनों में सुधार हुआ है।

बीजेडी ने फॉर्म 17सी पर ईसीआई की चूक और वोटों में भारी उछाल को लेकर चिंता जताई

भुवनेश्वर ०८/०८ (संवाददाता): ओडिशा में हुए दोहरे चुनावों के उन्नीस महीने बाद, बीजू जनता दल (बीजेडी) ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा फॉर्म 17सी और वोटों में अचानक हुई बढ़ोतरी से संबंधित खामियों का मुद्दा उठाया। बीजेडी ने पूर्ण पारदर्शिता की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 के ओडिशा चुनावों से संबंधित प्रमुख चिंताओं पर अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता संतृप्त मिश्रा और लेखाश्री सामंता सिंघर ने इस बात पर जोर दिया कि नवीन पटनायक की ओर से उठाई गई मांगें लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं, न कि राजनीति को।फॉर्म 17सी अभी भी लापता है- 19 महीने बीत जाने के बाद भी बूथवार मतदान के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं हुए हैं।

मतदान में विसंगतियां- डाले गए वोटों (फॉर्म 17सी) और गिने गए वोटों (फॉर्म 20) के बीच बड़ा अंतर है, कुछ बूथों पर 600 से अधिक अतिरिक्त वोट दिखाए गए हैं। शाम 5 बजे के बाद मतदान में अचानक उछाल- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के आंकड़ों में 7त्न से 30त्न की वृद्धि - जो पहले के चुनावों में नहीं देखी गई थी - अभी भी अस्पष्ट है।

खोए हुए वोट- ईवीएम/प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण मतपत्र अमान्य घोषित किए गए, और इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई।पारदर्शिता की मांग- बीजेडी ने ईवीएम ऑडिट में पार्टी की भागीदारी और मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग की है।

पार्टी ने चुनाव आयोग से जनता का विश्वास बहाल करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र और स्पष्ट स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया।

बार के अंदर हंगामा करने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

भुवनेश्वर ०८/०८ (संवाददाता):मंचेश्वर पुलिस ने शहर के पलासुनी इलाके के एक बार में हिंसक हंगामे और जबरन वसूली की कोशिश के सिलसिले में चार लोगों को गिरज़्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 1 जनवरी, 2026 की रात को मंचेश्वर पुलिस की सीमा के तहत रसूलगढ़ में एक बार के पास हुई। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है, वे हैं पूर्ण चंद्र शियाल (25), देबी प्रसाद बारिक (21), प्रियब्रत खटुआ (22) और आशुतोष मोहंती। पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी, दो अन्य लोगों के साथ, नशे की हालत में रसूलगढ़ के पास एक बार में घुसे और बार स्टाफ से पैसे मांगे।

ज़्लैकमेल और उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली

कोरापुट ०८/०८ (संवाददाता):ओडिशा के कोरापुट जिले के दासमनपुर ज़्लॉक के गाडियागुड़ा इलाके में एक छात्रा ने कथित तौर पर लगातार मानसिक उत्पीड़न और ज़्लैकमेल का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई है और युवा छात्रों के उत्पीड़न और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, छात्रा को कथित तौर पर लगातार मानसिक यातना, धमकियों और ज़्लैकमेल का शिकार बनाया जा रहा था, जिससे वह कथित तौर पर गंभीर तनाव में आ गई थी। परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उत्पीड़न कुछ समय से चल रहा था, जिससे पीड़िता पर बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा था।

परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, छात्रा पर बार-बार उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिससे वह गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव में थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि बदमाश उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर कर रहे थे, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हुई। यह घटना तब सामने आई जब लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद ज़्लैकमेल और उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे उत्पीड़न के आरोपों सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्तृत जांच चल रही है और आश्वासन दिया कि जांच के नतीजों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है, निवासी न्याय और छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है।

पीने के पानी की कमी को लेकर ग्रामीणों ने सड़कें जाम कीं

बालासोर ०८/०८ (संवाददाता): बैंचा और नारनपुर के बीच वाहनों की आवाजाही लगभग तीन घंटे तक ठप रही, ज़्योंकि नीलगिरी ज़्लॉक के मटियाली पंचायत के आदिआसाही, डंबुरिया और रामसिंह साही गांवों के गुस्साए ग्रामीणों ने इलाके में पीने के पानी के संकट का तुरंत समाधान करने की मांग को लेकर आदिअखुंटा चौक पर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे से सड़क पर बर्तन, बाल्टी और कंटेनर रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मटियाली से सिर्फ एक किलोमीटर दूर एक मेगा जल आपूर्ति परियोजना स्थापित की गई है। हालांकि, इन गांवों में पानी की आपूर्ति अनियमित बनी हुई है।ग्रामीणों ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे इलाके में पीने के पानी के संकट को हल करने के लिए स्थायी उपाय करे।

जूनियर इंजीनियरों के साथ स्थानीय पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया।

आईआईटी भुवनेश्वर की स्टडी में विश्वसनीयता, ऑपरेशनल दक्षता, तकनीकी प्रगति और ग्राहक-केंद्रितता में सुधारों को मान्यता दी गई

भुवनेश्वर ०८/०८ (संवाददाता): इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेज़्नोलॉजी (आईआईटी) भुवनेश्वर ने टाटा पावर और ओडिशा सरकार के जॉइंट वेंचर TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीज़्यूशन लिमिटेड (TPCODL) के पावर डिस्ट्रीज़्यूशन परफॉर्मेंस पर एक स्टडी जारी की है। इसमें जांच की गई है कि डिस्ट्रीज़्यूशन सेज़्टर में सुधारों के बाद पांच साल की अवधि में नेटवर्क की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल दक्षता, तकनीकी हस्तक्षेप और ग्राहक सेवा डिलीवरी में कैसे बदलाव आया है। यह स्टडी लगातार पूंजी निवेश, नेटवर्क आधुनिकीकरण और डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क में डिजिटल टेज़्नोलॉजी को अपनाने के परिणामों का मूल्यांकन करती है।

यह स्टडी आईआईटी भुवनेश्वर के इलेज़्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, स्कूल ऑफ इलेज़्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज के प्रो. चंद्रशेखर भेडे (प्रोफेसर), डॉ. चंद्रशेखर पेरुमल्ला (एसोसिएट प्रोफेसर) और डॉ. अभिनीत प्रकाश (असिस्टेंट प्रोफेसर) ने तैयार की है। यह TPCODL के परफॉर्मेंस का आकलन करती है, जो सेंट्रल ओडिशा में 29,354 वर्ग किमी में 1.36 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करता है। यह विश्लेषण फील्ड निरीक्षण, सिस्टम डेटा के सत्यापन और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऑपरेशनल और उपभोक्ता सेवा प्रथाओं की समीक्षा पर आधारित है।

स्टडी का एक मुख्य निष्कर्ष आउटेज की अवधि में महत्वपूर्ण कमी है, जो समीक्षा अवधि में सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेज़्स (SAIDI) में लगभग 50 प्रतिशत के सुधार में परिलक्षित होता है। यह सुधार एक अधिक स्थिर और लचीले डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क को इंगित करता है, जिसे बेहतर फॉल्ट डिटेज़्शन, तेजी से फॉल्ट आइसोलेशन और बेहतर बहाली प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग दरों और ट्रांसफार्मर विफलता दरों में कमी में भी योगदान दिया है।

स्टडी में ऑपरेशनल दक्षता में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जिसमें एग्रीगेट टेज़्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) नुकसान सुधार अवधि की शुरुआत में लगभग 30 प्रतिशत से घटकर FY 25 में 18.94 प्रतिशत हो गया है। यह सुधार बेहतर ऑपरेशनल नियंत्रण, बेहतर बिलिंग प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई नेटवर्क दक्षता के कारण हुआ है, जिसे 33 kv फीडर में 44 प्रतिशत की वृद्धि, 11 kv फीडर में 42 प्रतिशत की वृद्धि और 250 सबस्टेशनों को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में एकीकृत करने से समर्थन मिला है। पांच साल की अवधि में, 1,500 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश सबस्टेशनों को मजबूत करने, ऑटोमेशन कवरेज का विस्तार करने, डिजिटल निगरानी प्लेटफॉर्म तैनात करने और समग्र नेटवर्क लचीलेपन को बढ़ाने की दिशा में किया गया है। स्टडी में बताया गया है कि साइज़्लोन से निपटने वाले डिस्ट्रीज़्यूशन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए किए गए खास प्रयासों, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और रिडंडेंसी प्लानिंग शामिल है, के कारण साइज़्लोन से प्रभावित इलाकों में 24 से 48 घंटों के भीतर बिजली बहाल हो गई है, जो बेहतर तैयारी और रिस्पॉन्स क्षमता को दिखाता है।

कस्टमर सेंट्रिकिटी और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के विकास पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। स्टडी में कस्टमर सर्विस के तरीकों के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 24×7 कॉल सेंटर और 20 कस्टमर केयर सेंटर, कई डिजिटल पेमेंट ऑप्शन की उपलज़्धता और शिकायतों, सर्विस रिक्वेस्ट और जानकारी फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। बिलिंग की सटीकता में सुधार, प्रोविजनल बिलिंग में काफी कमी और कस्टमर के साथ एज़्टिव कज़्युनिकेशन ने पारदर्शिता, कस्टमर के भरोसे और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

डिसेंट्रलाइज्ड फॉल्ट रिस्पॉन्स को सर्विस में सुधार का एक महत्वपूर्ण जरिया माना गया है, खासकर भौगोलिक रूप से फैले हुए इलाकों में। शहरी इलाकों में 131 ज़्यूज कॉल सेंटर और ग्रामीण इलाकों में 811 कॉल सेंटर का नेटवर्क पूरे लाइसेंस एरिया में पहले लेवल के फॉल्ट रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण सिस्टम के साथ डिजिटल रूप से इंटीग्रेटेड रहता है। इन सेंटरों के ग्रामीण इलाकों में विस्तार से ग्रामीण जगहों पर ऐतिहासिक रूप से लंबे रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में मदद मिली है, जिससे FY25 में कस्टमर सैटिस्फैज़्शन स्कोर 96 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

यह स्टडी TPCODL के परफॉर्मेंस को व्यापक राष्ट्रीय पावर सेज़्टर सुधार फ्रेमवर्क के तहत रखती है, और यह नोट करती है कि यह दक्षता, कस्टमर सेंट्रिकिटी और विज़ीय स्थिरता पर राष्ट्रीय बिजली नीति के उद्देश्यों के साथ-साथ प्रस्तावित बिजली अधिनियम संशोधनों के इरादे के अनुरूप है, खासकर जवाबदेही और डिस्ट्रीज़्यूशन दक्षता के संबंध में। यह तालमेल TPCODL की बिजली मंत्रालय द्वारा 14वीं वार्षिक इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में A+ रेटिंग में झलकता है, जो ऑपरेशनल, विज़ीय और कस्टमर-केंद्रित परफॉर्मेंस में उत्कृष्टता के लिए लगातार तीन वर्षों तक टॉप-टियर मान्यता को दर्शाता है।